



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 वैशाख 1945 (श0)

(सं0 पटना 394) पटना, सोमवार, 15 मई 2023

सं० पी.पी.एम. 26/2023-12

कृषि विभाग

संकल्प

13 मई 2023

विषय:— कृषि रोड मैप 2023-2028 का 162268.78 करोड़ (एक लाख बासठ हजार दो सौ अड़सठ करोड़ अठहत्तर लाख) रुपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की सैद्धांतिक स्वीकृति।

कृषि रोड मैप 2023-2028 अंतर्गत प्रमुख उद्देश्यों यथा खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, समावेशी विकास के तहत रैयत किसानों के साथ-साथ गैर रैयत एवं महिला किसानों को बढ़ावा, सतत विकास की परिकल्पना, कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का प्रयोग, पर्यावरण को अक्षुण्ण रखने का संकल्प, छोटा किसान-बड़ा फार्मिंग अर्थात् किसानों का संगठन बनाकर उनके विकास का कार्य, कृषि उत्पादन के दौरान एवं उत्पादन के पश्चात क्षति को कम करने के लिए विशिष्ट कार्यघटक, टाल एवं दियारा तथा चौर के विकास के लिए विशिष्ट कार्यक्रम, आधारभूत संरचना आदि क्षेत्रों में व्यापक निवेश इत्यादि को परिलक्षित किया गया है।

इस रोड मैप के कार्यान्वयन के फलस्वरूप कृषि उत्पादों के उपज में वृद्धि होगी, कृषि उपज के भंडारण, प्रसंस्करण क्षमता का विस्तार होगा, कृषि उत्पादों यथा बीज, सिंचाई, तकनीकी परामर्श आदि सुलभता से किसानों को प्राप्त होगा, पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी, जलवायु परिवर्तन की परिस्थितियों से मुकाबला करने में किसान सक्षम होंगे एवं किसानों की आमदनी बढ़ेगी।

कृषि रोड मैप का सूत्रण दो भागों में किया गया है -

- कृषि रोड मैप का विजन डाक्यूमेंट - विजन डाक्यूमेंट में विभाग के चालू योजनाओं के साथ-साथ प्राथमिकता क्षेत्र के डी.पी.आर. को अंकित किया गया है।
- डी.पी.आर.-कृषि रोड मैप के प्राथमिकताओं को डी.पी.आर. (विस्तृत परियोजना प्रस्ताव) के रूप में आलेखित किया गया है।

चतुर्थ कृषि रोड मैप में शामिल विभिन्न विभागों के प्रमुख हस्तक्षेपों /कार्यघटकों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है-

- ❖ कृषि-फसल एवं बागवानी प्रक्षेत्र का विकास के अधीन बीज विकास / फसल विविधिकरण एवं सघनीकरण/दलहन एवं तेलहन हेतु मिशन/ पौधा संरक्षण/जैविक प्रोत्साहन कार्यक्रम/ कृषि बाजार व्यवस्था सुधार/ भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रम/ कृषि यांत्रिकरण/ जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम/

बागवानी विकास/ कृषि में आधुनिक तकनीक का प्रयोग/ कृषि शिक्षा/ कृषि अनुसंधान/ कृषि प्रसार/ जोखिम शमन/प्रबंधन/ निगरानी एवं मूल्यांकन सेल का गठन से सम्बंधित कार्यक्रम कार्यान्वित किये जायेंगे।

- ❖ **पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग** के अधीन गव्य विकास/ कुक्कुट विकास कार्यक्रम/ बकरी प्रक्षेत्र का सुदृढीकरण एवं विकास/ सूकर विकास योजना/ भैंस अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना/ अनुवांशिक सुधार केन्द्र की स्थापना/वन हेल्थ प्लेटफॉर्म की स्थापना/देशी मवेशियों के संरक्षण और अनुवांशिक सुधार केन्द्र की स्थापना/गोजातीय नस्ल सुधार कार्यक्रम का सुदृढीकरण/ राज्य स्तर पर सोसायटी का गठन—बिहार सोसाइटी फॉर एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (B-SAHMAT) / पशुपालन प्रशिक्षण और प्रसार की योजना/ बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएँ/ मात्स्यिकी विकास से सम्बंधित कार्यक्रम कार्यान्वित किये जायेंगे।
- ❖ **ऊर्जा विभाग** के अधीन 4.80 लाख विद्युत पम्प सेटों को मुफ्त कृषि विद्युत संबंध प्रदान किया जायेगा/मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना – 2 अन्तर्गत 12430 सर्किट कि०मी० डेडिकेटेड 11 के०भी० फीडर, 31078 वितरण ट्रांसफॉर्मर (25/63 के०भी०ए०) तथा 22717 सर्किट कि०मी०एल०टी० लाईन का निर्माण किया जायेगा/कृषि के लिये सभी 1354 अर्द्ध मौजूदा डेडिकेटेड फीडरों के सोलराइजेशन का कार्य से सम्बंधित कार्यक्रम कार्यान्वित किये जायेंगे।
- ❖ **राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग** के अधीन राज्य के 30 जिले जिनका Geo-Referenced मानचित्र उपलब्ध नहीं है वहाँ कुल 36020 राजस्व ग्रामों के 104252 शीट/मानचित्रों पर Geo-referencing का कार्य किया जायेगा /इसके अतिरिक्त चालू योजनाओं अंतर्गत सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम आदि से सम्बंधित कार्यक्रम कार्यान्वित किये जायेंगे।
- ❖ **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग** के अधीन प्राकृतिक वनों में हरित आवरण का विकास/ प्राकृतिक वनों के बाहर सरकारी भूमि पर हरित आवरण का विकास/ कृषि वानिकी एवं अन्य/बाँस रोपण/ पौधशालाओं का विकास/ प्राकृतिक वनों में मृदा एवं जल संरक्षण/ बाँस परियोजना/ बिहार वानिकी शोध एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुंगेर/ आर्द्रभूमियों का संरक्षण एवं विकास/ वन उत्पाद आधारित उद्योग का विकास/ कृषि वानिकी और गैर इमारती वन पदार्थों के उत्पाद के लिए विपणन और प्रबंधन आदि से सम्बंधित कार्यक्रम कार्यान्वित किये जायेंगे।
- ❖ **लघु जल संसाधन विभाग** के अधीन आहर पर्जन्य का जीर्णोद्धार / वीयर/चेक डैम का निर्माण/नवीकरण/ उद्भवह सिंचाई योजनाओं का निर्माण एवं जीर्णोद्धार/ निजी नलकूप योजना/ शैलो नलकूप योजना/ राजकीय नलकूप की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार योजना से सम्बंधित कार्यक्रम कार्यान्वित किये जायेंगे।
- ❖ **जल संसाधन विभाग** के अधीन प्रस्तावित पम्प नहर योजना/ प्रस्तावित जलाशय योजना/ नदी जोड़ योजना/ प्रस्तावित बाढ़ नियंत्रण योजना/ प्रस्तावित जल निस्सरण की योजनाएँ / हर खेत तक सिंचाई का पानी का कार्यक्रम/ निर्माणाधीन बराज योजना/ निर्माणाधीन वीयर योजना/ निर्माणाधीन पम्प नहर योजना/ निर्माणाधीन नहर पुनर्स्थापन/विस्तारीकरण योजना/ निर्माणाधीन जलाशय योजना/ टाल विकास योजना/ निर्माणाधीन बाढ़ नियंत्रण योजना/ निर्माणाधीन जल निस्सरण योजना से सम्बंधित कार्यक्रम कार्यान्वित किये जायेंगे।
- ❖ **उद्योग विभाग** के अधीन विकिरण इकाई की स्थापना/पैक हाउस की स्थापना/ उत्पादन समूहों में प्रसंस्करण इकाई/ मक्का स्टार्च इकाई/ मिश्रित फीड इकाइयों की स्थापना/ इथेनॉल इकाइयों (मक्का/टूटा हुआ चावल)/ छोटे पैमाने पर पोल्ट्री और पशु आहार इकाई की स्थापना/विस्तार/नए उबले चावल मिलिंग यूनिट कर उन्नयन/ मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की स्थापना/ ग्रेड ए गोदामों की स्थापना/SIPB से मंजूरी के तहत गोदामों की स्थापना/ मेगा फूड पार्क की स्थापना/खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना से सम्बंधित कार्यक्रम कार्यान्वित किये जायेंगे।
- ❖ **ग्रामीण कार्य विभाग** के अधीन अनजुड़े योग्य बसावटों को विभिन्न योजनाओं के तहत संपर्कता प्रदान करना/ ग्रामीण क्षेत्रों में जल-जमाव वाले क्षेत्रों से जल निकासी कर कृषि योग्य बनाने के लिए ग्रामीण पथों में अतिरिक्त संरचना का निर्माण से सम्बंधित कार्यक्रम कार्यान्वित किये जायेंगे।
- ❖ **खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग** के अधीन धान की अधिप्राप्ति @45 लाख मिट्टीक टन/वर्ष, गेहूँ की अधिप्राप्ति @20 लाख मिट्टीक टन/वर्ष, प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत तिलहन की अधिप्राप्ति, दलहन की अधिप्राप्ति/ भंडारण क्षमता का विकास—विभागीय /भंडारण क्षमता का विकास — पी.ई.जी. से सम्बंधित कार्यक्रम कार्यान्वित किये जायेंगे।

- ❖ गन्ना उद्योग विभाग के अधीन गुड़ विकास कार्यक्रम (डी.पी.आर.) एवं कतिपय चालू योजनायें कार्यान्वित किये जायेंगे।
- ❖ सहकारिता विभाग से संबंधित शहद उत्पादन का डी.पी.आर. बागवानी के साथ कन्वर्जेंस के माध्यम से कार्यान्वित किया जायेगा।

2. कृषि रोड मैप में शामिल विभाग/कार्यक्रमों के डी.पी.आर. एवं चालू योजना का कुल अनुमानित व्यय निम्नवत है —

(राशि करोड़ रु० में)			
चतुर्थ कृषि रोड मैप शामिल विभाग/ क्षेत्र का कार्यघटक	डी०पी०आर०	चालू योजना	अनुमानित व्यय
कृषि-फसल एवं बागवानी क्षेत्र विकास	11648.07	10718.11	22366.18
पशु एवं मत्स्य संसाधन	13042.15	2307.25	15349.40
ऊर्जा	6190.75	0.00	6190.75
राजस्व एवं भूमि सुधार	13.53	1187.21	1200.75
पर्यावरण, वन, एवं जलवायु परिवर्तन	3875.98	0.00	3875.98
उद्योग	3446.20	0.00	3446.20
गन्ना उद्योग	63.25	666.69	729.94
जल संसाधन	500.00	18696.17	19196.17
लघु जल संसाधन	5308.00	0.00	5308.00
ग्रामीण कार्य	393.98	0.00	393.98
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	5638.94	78128.00	83766.94
सहकारिता	0.00	444.50	444.50
कुल	50120.85	112147.93	162268.78

3. राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा कृषि रोड मैप पर प्राप्त सैद्धांतिक स्वीकृति के उपरांत कृषि रोड मैप में शामिल कार्यक्रमों को चालू योजना के रूप में संबंधित विभाग कार्यान्वित कर सकेंगे। इसके लिए संबंधित विभाग द्वारा योजना उद्ध्य एवं बजट उपबंध के अधीन स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जायेगा। विभागों के द्वारा कृषि रोड मैप के डी.पी.आर. के कार्यान्वयन को प्राथमिकता दी जायेगी। तदनुसार उपलब्ध योजना उद्ध्य एवं बजट उपबंध का व्यय सर्वप्रथम डी. पी.आर. के कार्यान्वयन के लिए किया जायेगा। डी.पी.आर. के कार्यान्वयन के उपरांत राशि अवशेष रहने पर ही चालू योजना कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जायेगा।

4. जिन कार्यक्रमों/डी.पी.आर. में पद सृजन अथवा वाहन क्रय का प्रस्ताव होगा, उन्हें राज्य सरकार के द्वारा विहित प्रावधान के आलोक में लोक वित्त समिति एवं मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

5. योजना कार्यान्वयन के संबंध में यथावश्यक निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कृषि रोड मैप से संबंधित समिति के द्वारा लिया जायेगा।

6. उक्त प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक 12.05.2023 को प्राप्त है, जो संचिका संख्या —पी.पी. एम. 26/2023 के पृष्ठ सं०—16/टि० पर संघारित है।

7. प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार का सहमति दिनांक 13.05.2023 को प्राप्त है, जो संचिका संख्या —पी.पी. एम. 26/2023 के पृष्ठ सं०—17/टि० पर प्राप्त है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० बी० राजेन्द्र,
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 394-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>